

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 704/2024

रोहितेश गढवाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. महेश कुमार ओला, पटवारी, पटवार मंडल, नांगल, गोविंद, गोविंदगढ़, तहसील, चौमू, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक :

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल, नांगल, गोविंद, गोविंदगढ़, तहसील, चौमू, जयपुर में दिनांक 20.01.2023 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल भनौखर, तहसील कठुमर जिला अलवर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 225 कि.मी. दूर किया गया है। राजस्व मंडल की स्थानान्तरण नीति दिनांक 30.10.1993 (अनुलग्नक-3) के द्वारा पटवारियों के दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण नहीं किये जावे एवं दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो पूर्ण औचित्य बतलाते हुए संभागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण किये जावे। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नीति का उल्लंघन करते हुए स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया है जो विधि-विरुद्ध एवं अनुचित है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में शारीरिक अध्यापक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बागड़ों का बास, आष्टी कलां, जयपुर में कार्यरत हैं। राज्य सरकार की नीति रही है कि यदि पति-पत्नी दोनो राजकीय सेवा में हो तो उन्हें एक ही स्थान पर या आस-पास पदस्थापित किया जावे। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3112/2024 ढालचन्द

- बनाम राजस्व विभाग एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2024 के द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थानपन स्थान पटवारी के पद पर पटवार मंडल, नांगल, गोविंद, गोविंदगढ़, तहसील, चौमू, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
 4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर पटवार मंडल, नांगल, गोविंद, गोविंदगढ़, तहसील, चौमू, जयपुर में दिनांक 20.01.2023 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल भनौखर, तहसील कटुमर जिला अलवर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। डॉ० अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उद्धृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या-4 को उसकी स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रत्यर्थी संख्या-4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ० अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।
 5. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to

be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 225 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

- 7.
8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
9. आदेश आज दिनांक को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य